

हा आधिकारिक दस्तावेज है। वित्त वर्ष 2016-17 में पर अमल करना है।

ई-नाम से किसानों को मिल रहा मुनाफे का इनाम

इससे किसानों की उपज जल्द बिक भी जाती है और उन्हें भुगतान भी तुरंत हो जाता है

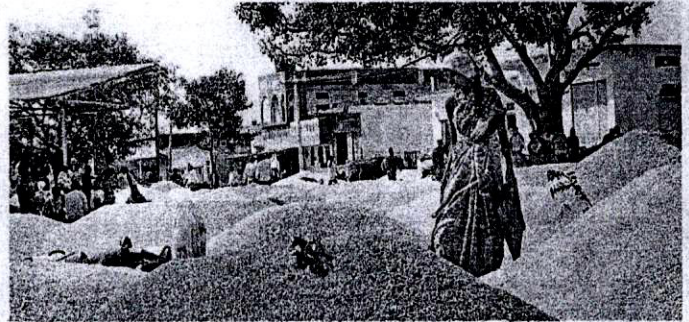
प्रेट, नई दिल्ली : किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन बोली प्लेटफॉर्म 'इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट' यानी ई-नाम किसानों के लिए सही मायनों में इनाम साबित हो रहा है। मंडी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अपने उत्पादों के बेहतर दाम और समय पर भुगतान की उम्मीद में ज्यादा से ज्यादा किसान ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे हैं। उन्हें इसका फायदा मिल भी रहा है।

ज्यादातर किसान अब भी अधिकृत होलसेल मंडी के आदतियों या आधिकारिक कमीशन एजेंट के जरिये ही ऑनलाइन बोली लगा रहे हैं, लेकिन ई-नाम पर उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा किसान खुद ऑनलाइन बोली लगाने के प्रति आश्वस्त होते जाएंगे। सरकार ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं। सरकार ने अप्रैल, 2016 में ई-नाम की शुरुआत की थी। वर्तमान में 14

14 राज्यों की 480 होलसेल मंडियां जुड़ चुकी हैं ई-नाम प्लेटफॉर्म से

राज्यों की ऑनलाइन फसल बोली लगाने वाली करीब 480 मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान देशभर की सभी 585 पंजीकृत मंडियों को ई-नाम से जोड़ना है। तेलंगाना स्थित सूर्यपिट होलसेल मंडी के सचिव येल्लैया ने कहा, 'हम पूरी तरह से ऑनलाइन नीलामी से जुड़ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें न सिर्फ उनकी उपज की अच्छी कीमत मिल रही है, बल्कि तुरंत भुगतान भी कर दिया जाता है।'

येल्लैया ने कहा कि ई-नाम से पहले फसली मौसम में कृषि उत्पादों की खुली बोली लगाना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो फसल का भंडार जमा हो जाता था, ऊपर से तौलने, मात्रा का अंदाजा लगाने और गुणवत्ता की जांच करने की भी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया,



'पहले किसान मंडियों में अपनी उपज नीलामी के लिए ले आते थे और उपज की बिक्री व भुगतान हो जाने तक इंतजार करते रहते थे। इस प्रक्रिया में दो-तीन दिन का वक्त लग जाता था। उतने दिनों के लिए गरीब किसान को रहने और खाने-पीने आदि के मद में होने वाला खर्च खुद ही वहन करना पड़ता था। ई-नाम ने इस पूरी थकाऊ व्यवस्था को बदल दिया है। अब तो

सूर्यपिट मंडी में धान, दालों, ज्वार और इस तरह के कुल नौ कमोडिटीज की नीलामी महज एक झटके में ऑनलाइन माध्यम से हो जाती है।'

येल्लैया ने कहा कि इस नई व्यवस्था से किसान भी खुश हैं, क्योंकि एक तो वे उसी दिन उपज की बिक्री कर वापस घर लौट सकते हैं। दूसरे, उन्हें हाथ के हाथ उपज का उचित दाम भी मिल जाता है।